

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 355, पृष्ठ 12)
कार्तिक, स्नान दान व्रत पूर्णिमा संवत् 2083
मंगलवार, 24 नवम्बर 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com

भोपाल संस्करण

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित



राजधानी... उज्जैन में बनेगा डीप टेक रिसर्च एवं इनोवेशन पार्क ...



खेल... मुंबई इंडिया को बेहतर प्रदर्शन कर अपने को साबित...



व्यापार... सर्राफा बाजार में सांकेतिक गिरावट, सोना और...



देश-विदेश... एशिया में बढ़ा भारत का दबदबा तीसरे ...

प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने दिखाई हरी झंडी

अयोध्या-जनकपुर के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस शुरू, पहले ही दिन 1,158 यात्रियों ने की यात्रा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भगवान राम की नगरी अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर के बीच सोमवार से सरयू-कमला एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने दिल्ली से आभासी माध्यम से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन रवाना की। पहले सफर में ट्रेन निर्धारित समय से करीब 20 मिनट पहले शाम 4:50 बजे गोरखपुर पहुंची। उत्तर प्रदेश और बिहार के 10 स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। पहले दिन 1,158 यात्रियों ने यात्रा की। आम यात्रियों के लिए सेवा 28 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है। अयोध्या से जनकपुर तक का सफर करीब 19 घंटे में पूरा होगा।



मोदी ने सुनी गुरबाणी



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल आवास में आयोजित प्रकाश पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने शबद कीर्तन में हिस्सा लिया और गुरबाणी सुनी। प्रधानमंत्री पहली बार उपराज्यपाल आवास पहुंचे। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मंगलवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर शबद कीर्तन के माध्यम से उनकी शिक्षाओं और संदेशों को याद किया गया।

भारत नेपाल को देगा 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को नेपाल के पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक विकास के लिए 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये के सहयोग पैकेज की घोषणा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध केवल पड़ोसी देशों के नहीं, बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति, आस्था और विश्वास पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने धारचूला सड़क पुल का उद्घाटन और बनबसा में एकीकृत जांच चौकी का शिलान्यास किया। नेपाल में दोधारा-चांदनी जांच चौकी का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा। नेपाल को कांडला और पारादीप बंदरगाहों तक पहुंच उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। ऊर्जा क्षेत्र में निम्न अरुण जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई। अरुण-3 परियोजना को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के दूसरे चरण का लोकार्पण और झापा पेट्रोलियम भंडारण केंद्र का शिलान्यास किया गया। नेपाल में उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र, नवाचार केंद्र और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का परिसर स्थापित किया जाएगा। नेपाली विद्यार्थियों के लिए विधि और प्रौद्योगिकी विषयों में छात्रवृत्तियां बढ़ाई जाएंगी। कृषि आधारित औद्योगिक पार्क, खेल सुविधाओं और क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में भी भारत सहयोग करेगा।

जनवरी से शुरू होगी योजना, 54 लाख युवाओं को मिलेगा लाभ

बंगाल में बेरोजगार स्नातकों को 2,000 और गैर-स्नातकों को 1,500 रुपये भत्ता

नईदुनिया ब्यूरो, कोलकाताः पश्चिम बंगाल सरकार जनवरी से बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए भरोसा कर्मसूची योजना शुरू करेगी। इसके तहत स्नातक और डिप्लोमा धारकों को हर महीने 2,000 रुपये तथा गैर-स्नातक युवाओं को 1,500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सरकारी व्यावसायिक संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त युवाओं को भी मिलेगा। योजना के लिए 21 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवा पात्र होंगे। सरकार ने वर्ष 2028-29 से सहायता राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। इसके बाद स्नातक और डिप्लोमा धारकों को प्रतिमाह 3,000 रुपये तथा गैर-स्नातकों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि नई योजना पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की युवासाथी योजना की जगह शुरू की जा रही है। पिछली सरकार की योजना के 54 लाख मौजूदा



लाभार्थियों का सत्यापन 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। योजना के तहत भत्ते की राशि प्रत्येक महीने के दूसरे सप्ताह में लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी। इसकी औपचारिक शुरुआत फरवरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान होगी। एक परिवार से अधिकतम दो सदस्य इस योजना का लाभ ले सकेंगे। वहीं, अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपये की सहायता प्राप्त करने वाले लोग इस भत्ते के पात्र नहीं होंगे।

पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंग होगा

पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर पश्चिम बंग किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि नौ दिसंबर को विधानसभा में नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रस्ताव विधानसभा से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। देश में अब तक छह राज्यों के नाम बदले जा चुके हैं। वर्ष 2026 में केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया था।

खास-खबरें

भाजपा विधायक रेखा पात्रा ने खाया जहर

नईदुनिया ब्यूरो, कोलकाता: पश्चिम बंगाल की भाजपा विधायक रेखा पात्रा ने शनिवार रात जहरीला पदार्थ खा लिया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और पिछले दो दिनों से कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पहले उन्हें जीवनरक्षक प्रणाली पर रखा गया था, सोमवार सुबह इससे हटा दिया गया। हालांकि, शरीर में जहर का असर अब भी बना हुआ है और हृदय गति सामान्य से अधिक है। उनके पति संदीप पात्रा के अनुसार, फिलहाल उनकी स्थिति ठीक नहीं है। रेखा वर्ष 2024 में संदेशखाली आंदोलन के दौरान चर्चा में आई थीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी उनसे फोन पर बातचीत कर उनके संघर्ष की सराहना की थी।

गोधरा अग्निकांड के दोषी को जमानत

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषी इरफान सिराज पाड़ा की सजा निलंबित करते हुए चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी। गुजरात सरकार ने उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर आपत्ति नहीं जताई। इरफान करीब 17 वर्षों से जेल में बंद है। इस मामले में कुल 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें अब तक 11 को जमानत मिल चुकी है। गौरतलब है कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 डिब्बे में आग लगने से 58 लोगों की मौत हुई थी। मार्च 2011 में निचली अदालत ने 31 आरोपितों को दोषी ठहराया था। इनमें 11 को मृत्युदंड और 20 को आजीवन कारावास मिला था। वर्ष 2017 में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

देश की सभी राजधानियों के नगर निगमों और नगर पालिकाओं से छह जनवरी तक मांगी विस्तृत रिपोर्ट

आज घर, कल होटल और फिर मॉल कैसे?: सुको



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के आवासीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताई है। सोमवार को लोगानाथन बनाम तमिलनाडु राज्य मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सवाल उठाया कि जिन स्थानों पर आज घर बने हैं, वहां अगले दिन होटल और फिर अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान कैसे खुल जाते हैं? न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना ऐसा संभव नहीं है। भोपाल के याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी के अनुसार, न्यायालय ने टिप्पणी की कि आवासीय क्षेत्रों का स्वरूप पूरे देश में बिगड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए केवल सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी ऐसे मामलों की सुनवाई करनी होगी। न्यायालय ने देश की सभी राजधानियों के नगर निगमों और नगरपालिकाओं से अवैध निर्माण तथा आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों को छह जनवरी तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।

न्यायालय ने सवाल उठाया कि अवैध निर्माण और भूमि उपयोग के उल्लंघन को आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है। त्रिपाठी के मुताबिक, न्यायालय ने कहा कि नगर निगम और नगरपालिका स्तर पर अवैध गतिविधियों के लिए मानो कीमत तय है। उसने यह भी पूछा कि ऐसी व्यवस्था बनाने वाले अधिकारी और प्राधिकारी कौन हैं। भोपाल नगर निगम ने सुनवाई के दौरान अपनी सीलिंग कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की। रहवासियों की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति सामने नहीं रखी गई। उन्होंने कार्रवाई में पक्षपात और प्रभावशाली लोगों को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि कई प्रतिष्ठान सील होने के बाद दोबारा खुल गए। भोपाल में करीब 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों का आंकड़ा सामने आया है। नगर निगम ने अब तक 8,084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए और 190 प्रतिष्ठानों को बंद कराया था।

कैबिनेट में विकास और जनकल्याण के लिए 7 हजार करोड़ की स्वीकृति

2279 करोड़ में बनेगा 'अद्वैत लोक'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जनकल्याण के लिए सात हजार करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई।

बैठक में ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में अद्वैत लोक के निर्माण के लिए 2,278 करोड़ 99 लाख रुपये मंजूर किए गए। इसके अलावा 46 हजार से अधिक घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 193 करोड़ 72 लाख रुपये की कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई। 'वेदान्त पीठ की स्थापना' के अंतर्गत ओंकारेश्वर में विकसित किये जा रहे एकात्म धाम में



'अद्वैत लोक' (शंकर संग्रहालय) में हाइस्क्रीन थियेटर, माया गैलरी, लेज़र लाइट वाटर एण्ड साउंड शो, अद्वैत नर्मदा विहार, निदिध्यासन केन्द्र, कला वीथिका, शंकर स्तम्भ, अन्नपूर्णा, कलाग्राम, पंचायतन मन्दिर आदि विभिन्न माध्यमों से आचार्य शंकर के जीवन योगदान एवं अद्वैत वेदान्त दर्शन को आगंतुकों,दर्शकों और श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और देशी गौवंश को बढ़ावा देने के लिए गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ गौपालकों को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50 हजार और तृतीय पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और देशी नस्लों का संरक्षण करना है।

46 हजार से अधिक घरों में पहुंचेगी बिजली

विद्युतीकरण योजना के पहले चरण में 1,834 बसाहटों के 46,574 घरों और 54 शासकीय संस्थानों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि देगी।

सहकारी बैंकों को मिलेगी आर्थिक सहायता

मंत्रिमंडल ने नौ कमजोर जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 325 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता स्वीकृत की है। वहीं, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लंबित चुनावों की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

सरकारी योजनाओं के लिए भी बजट मंजूर

मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग की 23 योजनाओं को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के लिए 3,059 करोड़ 7 लाख रुपये तथा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना के लिए 1,165 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसके अलावा खनिज अन्वेषण के कार्यों के लिए मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

दल-बदल कानून में बदलाव होः सुको

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून में बदलाव की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है।

याचिका में कहा गया है कि कई बार सांसद और विधायक अयोग्यता की कार्रवाई से बचने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इससे निर्वाचित सरकारों का बहुमत प्रभावित होता है और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले में विधि आयोग, कानून मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है।

याचिका में कहा गया है कि कई मामलों में विधायक और सांसद विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता पर निर्णय सुनाए जाने से पहले ही इस्तीफा दे देते हैं।

बिसलेरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी, दो प्रयोगशालाओं की जांच में नमूने असुरक्षित मिले

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ असुरक्षित पैकेज्ड पेयजल के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इससे कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। प्राधिकरण ने बिसलेरी सहित पैकेज्ड पेयजल बेचने वाले सभी बड़े ब्रांडों के पानी के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे हैं। प्राधिकरण के अनुसार, जांच में यदि किसी कंपनी के पानी के नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिसलेरी के मामले में कंपनी के पानी का एक नमूना लिया गया था। प्रयोगशाला की जांच में इसमें ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं पाई गई।

राजनीति रोकना हमारा काम नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजनीतिक नेताओं के बयानों से न्यायपालिका के कामकाज में बाधा पहुंचने के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि राजनीतिक दलों को अपना एजेंडा उठाने से कैसे रोका जा सकता है? राजनीति रोकना अदालत का काम नहीं है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने मामले को उस पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया, जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ एक वकील की आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े अवमानना मामले की सुनवाई कर रही है। यह याचिका दो अधिवक्ताओं अदिति यादव और विकास तिवारी ने दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ नेताओं, सांसदों और अन्य लोगों के बयानों से न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित हो रही है और न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

ट्रंप के फोन को किम जोंग उन ने किया नजरअंदाज

सियोल, एजेंसीः उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से किए गए फोन और भेजे गए पत्र का उत्तर कोरिया की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इस घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच संबंधों में जारी तनाव और गहरा गया है। एक अमेरिकी समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने पिछले वर्ष उत्तर कोरियाई नेता से संपर्क करने के लिए स्थापित दूरभाष माध्यमों और अन्य संचार व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया



था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उत्तर कोरिया अमेरिका से अपने परमाणु कार्यक्रम को स्वीकार करने की मांग कर रहा है। किम जोंग उन का मानना है कि अमेरिका यदि उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता देता है, तभी दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व संभव हो सकता है।

जेन्सन हुआंग फिर बने एनवीडिया के प्रमुख



कैलिफोर्निया, एजेंसीः अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया के प्रमुख जेन्सन हुआंग एक बार फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभालेंगे। कंपनी के निदेशक मंडल ने अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद उनकी वापसी का निर्णय लिया है। इस घोषणा के बाद कंपनी के शेयरों में 31 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई। हुआंग ने 12 नवंबर को कंपनी के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। कंपनी का कहना है कि हुआंग की वापसी से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

चेतावनी — गृह मंत्रालय की सलाह, काम खत्म होने पर लॉग आउट कर दें

वाट्स एप वेब चैट्स पर साइबर ठगों की नजर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः कंप्यूटर पर वाट्स एप वेब का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा संबंधी चेतावनी जारी की है। मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आगाह किया है कि किसी दूसरे या साझा कंप्यूटर पर वाट्स एप वेब का खाता खुला छोड़ना भारी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कोई अन्य व्यक्ति आपकी निजी बातचीत पढ़ सकता है। इतना ही नहीं, वह आपके नाम और पहचान का इस्तेमाल कर दूसरे लोगों को संदेश भेजने के साथ ही संपर्कों और समूहों की बातचीत तक पहुंच बना सकता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा



विश्लेषण इकाई ने 18 नवंबर 2026 को वाट्स एप वेब के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर परामर्श जारी किया था। इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर पर पहले से खुला हुआ खाता अनधिकृत पहुंच का रास्ता बन सकता है। इसका इस्तेमाल करके साइबर अपराधी निजी संदेशों और महत्वपूर्ण जानकारियों तक पहुंच सकते हैं।

साझा और सार्वजनिक कंप्यूटर पर विशेष सावधानी

साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कार्यालयों के साझा कंप्यूटर, सार्वजनिक कंप्यूटर, साइबर कैफे, होटल के व्यावसायिक केंद्र और उधार लिए गए कंप्यूटर पर वाट्सएप वेब का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी है। ऐसे उपकरणों पर सरकारी, वित्तीय, संगठन से जुड़ी या अन्य गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।

ब्राउजर बंद करने से लॉग आउट नहीं होता

परामर्श में सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि केवल ब्राउजर का टैब या खिड़की बंद कर देने से वाट्स एप वेब लॉग आउट होना सुनिश्चित नहीं होता। यदि किसी कंप्यूटर पर खाता खोलने के बाद बिना बाहर निकले ब्राउजर बंद कर दिया जाता है, तो उसका सक्रिय सत्र बना रह सकता है। बाद में उसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपकी बातचीत देख सकता है। इसका फायदा उठाकर साइबर अपराधी आपके परिचितों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को आपके खाते से संदेश भेज सकते हैं। वे आपकी पहचान का इस्तेमाल कर पैसों की मांग कर सकते हैं या संदिग्ध संदेश और कड़ियां भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चूंकि संदेश आपके वास्तविक खाते से आता है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति उस पर आसानी से भरोसा कर सकता है।

फोन से भी कर सकते हैं जांच

उपयोगकर्ता अपने फोन में वाट्सएप खोलकर जुड़े उपकरणों की सूची देख सकते हैं। एंड्रॉयड फोन में ऊपर दाईं ओर दिए गए तीन बिंदुओं वाले विकल्प से जुड़े उपकरणों तक पहुंचा जा सकता है। आईफोन में यह सुविधा सेटिंग्स के भीतर उपलब्ध है। सूची में किसी अनजान या इस्तेमाल नहीं किए जा रहे उपकरण का नाम दिखाई देने पर उसे चुनकर तुरंत खाते से बाहर निकलना चाहिए।